3 निर्धनता एक चुनौती

प्रश्न 1. बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिये-
(प्रत्येक के लिये 1 अंक)

(i) निर्धनता का अर्थ है-
(अ) भुखमरी और आशय का न होना
(ब) नियमित रोजगार का अभाव
(स) शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव (द) उपरोक्त सभी

(ii) भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के लिये कितनी है?
(अ) 2000 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
(ब) 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
(स) 2200 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
(द) 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

(iii) भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है-
(अ) वित्त मंत्रालय (ब) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन
(स) नीति आयोग (द) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

(iv) प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारम्भ की गई-
(अ) 1991 (ब) 1986 (स) 1995 (द) 1993

(v) 'काम के बदले अनाज योजना' प्रारम्भ की गई-
(अ) 2004 में (ब) 2002 में (स) 2005 में (द) 1991 में

(vi) भारत में खाद्य असुरक्षित वर्ग है
(अ) भूमिहीन (ब) पारम्परिक दस्तकार
(स) निराश्रित तथा भिखारी (द) उपरोक्त सभी

उत्तर- (i) ब, (ii) द, (iii) द, (iv) द, (v) स, (vi) द।

प्रश्न 2. सत्य/असत्य का चयन कीजिये-
(प्रत्येक के लिये 1 अंक)

(i) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरम्भ 1999 में किया गया।
(ii) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1995 में आरंभ हुयी।
(iii) कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित है।
(iv) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 का उद्देय ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर के निवासियों के लिये कम से कम 100 दिनों के लिये रोजगार उपलब्ध कराना है।
(v) भारत में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की सख्या सर्वाधिक है।
(vi) भारत में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात एक समान नहीं है।
(vii) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आरम्भ 1999 में किया गया।

उत्तर- (i) सत्य, (ii) असत्य, (iii) सत्य, (iv) सत्य, (v) सत्य, (vi) असत्य (vii) सत्य।

प्रश्न 3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये-
(प्रत्येक के लिये 1 अंक)

(i) भारत में देश का हर.....व्यक्ति निर्धन है।
(ii) भारत में नगरीय क्षेत्री में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता .....कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है।
(iii) सामाजिक अपवर्जन.....का कारण और परिणाम दोनों हो सकता है।
(iv) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोगार अधिनियम वर्ष.....में बना।
(v) वर्ष 2011-12 में भारत में लगभग ..... करोड़ लोग निर्धन थे।

उत्तर- (i) चौथा (ii) 2100 (iii) निर्धनता (iv) 2005 (v) 27 करोड़।

प्रश्न 4. एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिये-
(प्रत्येक के लिये 1 अंक)

(i) एन. एस. एस. ओ. का पूरा नाम क्या है?
(ii) केरल ने किस संसाधन के विकास पर अधिक ध्यान किया है?
(iii) मनरेगा का पूरा नाम लिखिए।
(iv) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ?
(v) भारत का सर्वाधिक निर्धन राज्य कौनसा है?
(vi) वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात कितने प्रतिशत था?
(vii) निर्धनता क्या है?
(viii) सामाजिक अपवर्जन क्या है?
(ix) भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है?
(x) निर्धनता रेखा से क्या आशय है?
(xi) निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है?
(xii) विकास शील देशों के बीच निर्धनता का आकलन किस प्रकार किया जाता है?
(xiii) भारत में सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाले दो राज्य के नाम लिखिए?
(xiv) उन दो देशों के नाम लिखिये, जहां निर्धनता अनुपात विश्व में सर्वाधिक है?
(xv) विश्व के उन दो देशों के नाम लिखिये, जहाँ निर्धनता अनुपात में गिरावट आई है?
(xvi) अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा क्या है?

उत्तर- (i) नेशनल सेम्पल सरवाइ ऑफिस (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन) (ii) मानव संसाधन, (iii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, (iv) 1 अप्रैल 1995 को। (v) छत्तीसगढ़, (vi) 1.91% (vii) निर्धनता, स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। (viii) निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों है। (ix) भारत में निर्धनता रेखा का आकलन वर्तमान सूत्र वांछित के आधार पर किया जाता है। (x) नागरिकों

के उस न्यूनतम आर्थिक स्तर से है जो उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। (xi) औरतें, बच्चे और वृद्ध। (xii) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा । (xiii) बिहार और झारखण्ड है। (xiv) गोवा और केरल। (xv) गोवा और हिमाचल प्रदेश । (xvi) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले को अंतरराष्ट्रीय निर्धनता रेखा कहते हैं।

प्रश्न 5. सही जोडी मिलाइए– **(प्रत्येक के लिये 4 अंक)**

कॉलम A	कॉलम B
(i) निर्धनता रेखा का आंकलन	(अ) 2004
(ii) भूमि सुधार	(ब) बिहार
(iii) प्रधानमंत्री रोजगार योजना	(स) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
(iv) उच्च कृषि वृद्धि वाला राज्य	(द) 2005
(v) राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना	(इ) 1993
(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी अधिनियम	(फ) 2000
(vii) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	(ग) पश्चिम बंगाल
(viii) सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य	(ह) पंजाब

उत्तर– (i) स, (ii) ग, (iii) इ, (iv) ह, (v) द, (vi) अ, (vii) फ, (viii) ब।

प्रश्न 8. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न/विश्लेषणात्मक प्रश्न– **(प्रत्येक के लिये 4 अंक)**

(1) भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय किन किन बातों पर विचार किया जाता है ? समझाइये।

उत्तर– निर्धनता का आकलन करते समय वाद कपड़ों, जूतो, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। इन भौतिक आवश्यकताओं का उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खादय आवश्यकता के लिए निर्धारित सूत्र कैलोरी की आवश्यकताओं पर आधारित है। भारत में निर्धारित कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है।

(2) उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें, जो भारत में निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है ?

उत्तर– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के परिवार उन सामाजिक समूहों में शामिल हैं, जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह, ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार है। इसके अलावा महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को अति निर्धन माना जाता है क्योंकि उन्हे मुल्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच से वंचित रखा जाता है।

(3) भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइये ?

उत्तर– भारत में अन्तर्राज्यीय नातक समान नहीं है। इसमें विभिन्नता के कारण निम्नलिखित है—

(1) विभिन्न राज्यों में जनसंख्या घनत्व एक समान नहीं है।
(2) राज्यों में प्राकृतिक में भी पाई जाती है।
(3) लोगों को शिक्षा के प्रतिशत में भी पर्याप्त भिन्नता है।
(4) जो राज्य ज्यादा समय तक गुलाम रहे यहाँ गरीबी भी ज्यादा समय तक रही।
(5) राज्य सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की कमी भी निर्धनता का एक कारण रही है।
(6) भौगोलिक अमसानता भी राज्यों में निर्धनता का मुख्य कारण है।

(4) भारत में निर्धनता के क्या कारण है ? लिखिये ।

उत्तर– भारत में निर्धनता के कारण कभी कभी अपनी जीविका चलाने के लिए आवश्यक वस्तुओं को एकत्र करना भी मुश्किल हो जाता है। आवश्यक वस्तुओं के अभाव में निर्धनता का सामना करना पड़ता है। उत्पादन के ठीक होने किंतु उसका वितरण असमान होने पर भी निर्धनता का जन्म होता है। उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का एकाधिकार होने पर अधिकांश लाभ वही ले जाते हैं। इस प्रकार आय की असमानता विद्यमान रहती है। अतः लोगों में निर्धनता भी विद्यमान रहती है।

(5) निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें?

उत्तर– सरकार की वर्तमान निर्धनता–निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता-निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। यह कई योजनाओं और कार्यक्रमों पर भी आधारित है। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है।

(i) राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम: यह कार्यक्रम 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है, जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है।

(ii) प्रधानमंत्री रोजगार योजना: इस कार्यक्रम को 1993 में आरम्भ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।

(iii) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम: इस कार्यक्रम को 1995 में आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। दसवी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया।

(iv) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना: इस कार्यक्रम को 2000 में आरम्भ किया गया। इस योजना क अंतर्गत गाँवों में मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(v) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005: इस अधिनियम को सितम्बर 2005 से पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण

रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर, रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।

(6) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है ? इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाइये।

उत्तर– भारतीय संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार शुरु करने के लिए प्रारम्भ की गई।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो गरीबों की जिंदगी में सीधे तौर पर जुड़ा है और जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसका मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना। इसके तहत हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी है। यह रोजगार शारीरिक श्रम के संदर्भ में है और उस वयस्क व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो इसके लिए राजी हो। इस अधिनियम का दूसरा लक्ष्य यह है कि इसके तहत टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाए और ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को मजबूत बनाया जाए। इस अधिनियम का मकसद सूखे जंगलों के कटान खुदा क्षरण जैसे कारणों से पैदा होने वाली निर्धनता की समस्या से भी निपटना है, ताकि रोजगार के अवसर लगातार पैदा होते रहें। मुख्य विशेषताएँ—

राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहें, कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा वेतन सोजगार मुहैया करवाएगी।

(7) वैश्विक निर्धनता परिदृश्य को स्पष्ट कीजिये ।

उत्तर– वैश्विक निर्धनता पर आँकड़े निम्न प्रवृत्तियों को दर्शा रहे हैं-

(i) विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन 1 डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले लोग अत्यंत आर्थिक निर्धनता के दायरे में आते हैं। 1 डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 28 प्रतिशत से गिरकर 2001 में 21 प्रतिशत हो गया है।

(ii) यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहत क्षेत्रीय भिन्नताएँ पायी जाती। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण-पूर्ण एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है।

(iii) भारत में भारत में गरीबी भी कम हो गई है, लेकिन कमी की जाति बहुत धीमी है। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार कुल आबादी का 35.3% अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है। गरीबी कम हो गई है, लेकिन कमी की गति बहुत धीमी है। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार कुल आबादी का 35.3% अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है।

(iv) सब-सहारा अफ्रीका में निर्धनता 1981 में 415% से बढ़कर 2001 में 46% हो गयी।

(v) रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्यापत हो गयी है।

(8) भारत में निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है ? 'इस कथन की व्याख्या कीजिये'।

उत्तर– भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है । यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है, निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। वर्ष 2011 12 भारत में निर्धनता अनुपात 22 प्रतिशत है।

(9) भारत सरकार द्वारा लागू किये गये लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की संक्षेप में व्याख्या कीजिये ।

उत्तर– सरकार द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए जो योजनाएँ बनाई गई है, इस प्रकार है— (i) अन्त्योदय अन्न योजना।

(ii) ग्रामीण विकास रोजगार योजना।

(iii) कार्य के बदले भोजन योजना, 2004

(iv) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, 2006

(v) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 1999

(vi) प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, 1993

(vii) प्रधानमन्त्री ग्रामोद्योग योजना, 2000

(10) भारत में निर्धनता में अंतर-राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका उचित है?

उत्तर– भारत में निर्धनता में अन्तर्राज्यीय असमानताओं का मुख्य विवरण इस प्रकार है—

क्रमांक	राज्य	गरीबी अनुपात का
1	बिहार	33.7
2	ओडिशा	32.6
3	असम	32
4	मध्यप्रदेश	31.6
5	उत्तर प्रदेश	29.4
6	कर्नाटक	20.9
7	पश्चिम बंगाल	20
8	महाराष्ट्र	17.4
9	गुजरात	16.6
10	राजस्थान	14.7
11	तमिलनाडु	11.3
12	हरियाणा	11.2
13	आन्ध्र प्रदेश	9.2
14	पंजाब	8.3
15	हिमाचल प्रदेश	8.1
16	केरल	7.1

उपर्युक्त तालिका अनुसार बिहार राज्य सबसे गरीब है।

(11) भारत में वो सामाजिक समूह कौन से है जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है ?

उत्तर– सामाजिक समूह- (i) अनुसूचित जाति के परिवार (ii) अनुसूचित जनजाति के परिवार।

(12) भारत में वो आर्थिक समूह कौन से है जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है ?

उत्तर– आर्थिक समूह- ग्रामीण कृषि, श्रमिक परिवार तथा नगरीय अनियत मजदूर परिवार।

(13) सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता के प्रमुख तीन सूचक कौन-कौन से है ?

उत्तर– (1) घर की कमी, (2) जातिवाद, (3) बढ़ती हुई जनसंख्या, (4) साक्षरता स्तर।

निर्धनता का अर्थ उस सामाजिक आर्थिक स्थिति से है जिसमें समाज का एक भाग जीवन स्वास्थ्य एवं दक्षता के लिए न्यूनतम उपभोग को जुटा पाने में असमर्थ होता है। जब समाज का बहुत बड़ा भाग न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित होकर केवल निर्वाह स्तर पर गुजारा करता है तो उसे ब्यापक निर्धनता' कहा जाता है।

(14) मानव निर्धनता से आप क्या समझते है ?

उत्तर– मानव निर्धनता से आप क्या समझते हर किसी व्यक्ति को निधन माना जाता है, यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं, जैसे भोजन, कपड़ा और आवास को पुरा करने के लिए आवश्यक है।

(15) राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है ? समझाइये

उत्तर– राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम को प्रचलित रूप से ' काम के बदल अनाज कहा जाता है, जिसे 2004 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के आठ राज्यों नामित- गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान के सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। खाद्य अनाज केन्द्रीय सरकार द्वारा इन आठ राज्यों को उपलब्ध कराए जाते हैं मजदूर राज्य सरकार, द्वारा आंशिक रूप से नकद और खाद्य अनाजों के रूप में दी जा सकती है।

(16) भारत में उन राज्यों की पहचान करे जहाँ निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है।

उत्तर– भारत में उडीसा, मध्यप्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है।

(17) भारत में गरीबी अन्मूलन के मार्ग में आने वालों कोई तीन चुनौतियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर– गरीबी उन्मुलन मार्ग में आने वाली चुनौतियाँ–

ग्रामीण शहरी क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित है।

यह पूरा न्यूनतम जीवन निर्वाह के 'उचित' स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के है। 'न्यूनतम' स्तर के विषय में है। 'अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है, कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार 'मानव निर्धनता' तक कर देना चाहिए।

(18) 'सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हो सकता है ?' इस कथन को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर– सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभ और अवसरों से अपवर्जित रहते है, जिनका उपभोग दूसरे (उनसे अधिक अच्छे) करते।